

न्यूज़ ड्रुडे

‘रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure: DAP) 2020’ का दूसरा मसौदा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया गया

○ रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) को पहले, रक्षा खरीद प्रक्रिया (Defence Procurement Procedure: DPP), 2020 के नाम से जाना जाता था। DAP के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय (Service Headquarters: SHQ) दोनों द्वारा किए जाने वाले सभी पूंजीगत अधिग्रहणों (चिकित्सा उपकरणों को छोड़कर) को समाविष्ट किया गया है। इसमें स्वदेशी स्रोतों तथा आयात-पूर्व (ex-import) दोनों माध्यमों से किए जाने वाले अधिग्रहण शामिल हैं।

➤ उल्लेखनीय है कि DPP 2020 (जिसे अब DAP नाम दिया गया है) का प्रथम मसौदा मार्च 2020 में जारी किया गया था। यह DPP, 2016 को प्रतिस्थापित करेगा।

○ इस मसौदे में शामिल प्रमुख बिंदु:

- पहली बार, कुछ विशिष्ट प्रकार के हथियारों एवं प्लेटफॉर्मों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।
- ❖ इसका प्रमुख उद्देश्य घरेलू और स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देना तथा DAP को आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ संरेखित (align) करना है।
- इसमें विदेशी विक्रेताओं से लाइसेंस प्राप्त करने सहित, भारत में विनिर्मित उपकरणों में स्वदेशी सामग्री के उच्च अनुपात को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। (इन्फोग्राफिक देखें)।
- ❖ एक नई खरीद श्रेणी, बाई (ग्लोबल-भारत में विनिर्माण) (Buy (Global-Manufacture in India)) प्रारंभ की गई है।
- अधिग्रहण हेतु एक नवीन श्रेणी के रूप में लीजिंग (पट्टा व्यवस्था) को समाविष्ट किया गया है, ताकि अत्यधिक आरंभिक पूंजीगत व्यय को आवधिक किराया भुगतान से प्रतिस्थापित किया जा सके।
- सॉफ्टवेयर तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communications Technology: ICT) पर आधारित उपकरणों और प्लेटफॉर्मों की खरीद के लिए एक नया अध्याय शामिल किया गया है।
- इसमें “अनुबंध के पश्चात् प्रबंधन” (post contract management) के संबंध में स्पष्ट प्रावधानों को शामिल किया है। यह अनुबंध की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।

INDIGENISATION TARGET FOR VARIOUS ACQUISITION CATEGORIES



Acquisition category	Indigenous content (IC)
Buy (Indian - Indian-Designed, Developed and Manufactured)	Indigenous design essential; ≥ 50% IC
Buy (Indian)	If indigenously designed, ≥ 50% IC; if foreign designed ≥ 60% IC
Buy and Make (Indian)	≥ 50% IC, calculated on the 'Make' portion
Buy and Make	≥ 50% IC
Buy (Global - Manufacture in India)	≥ 50% IC,
Buy (Global)	Foreign vendor- Nil IC requirement Indian vendor ≥ 30% IC

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस (29 जुलाई) के अवसर पर चतुर्थ बाघ अनुमान रिपोर्ट (4th Tiger Assessment Report) जारी की गई

- यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गयी है। इस रिपोर्ट में बाघों की स्थिति का आकलन संपूर्ण भारत में उनकी आबादी के स्थानिक वितरण और घनत्व के संदर्भ में किया गया है।
- इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:
 - वर्तमान में भारत में बाघों की कुल आबादी 2,967 है, जो वैश्विक बाघों की आबादी का 70 प्रतिशत है। बाघों की संख्या में प्रति वर्ष 6% (वर्ष 2006 से वर्ष 2018) की दर से वृद्धि परिलक्षित हुई है।
 - भारत के लगभग एक तिहाई बाघ टाइगर रिजर्व के बाहर अधिवासित हैं।
 - मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, इसके पश्चात् कर्नाटक का स्थान है।
 - पूर्वोत्तर भारत में बाघों की आबादी में कमी आई है। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में भी बाघों की आबादी में लगातार गिरावट आई है।
 - पश्चिमी घाट (नागरहोल-बांदीपुर-वायनाड-मुदुमलाई-सत्यमंगलम-BR) ब्लॉक में विश्व की सर्वाधिक शृंखलाबद्ध बाघ आबादी (लगभग 724 बाघ) पाई जाती है।
 - कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी है (वर्ष 2018 में लगभग 231)।
 - 50 में से लगभग 17 टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी के सतत भरण-पोषण के लिए लगभग अपनी क्षमता के शीर्ष पर हैं।
- इस रिपोर्ट को जारी करने के दौरान, टाइगर रिजर्व के भीतर जल और चारे की उपलब्धता के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई ताकि कम से कम जानवर इन रिजर्व से बाहर निकल सकें और मानव-पशु संघर्ष को कम किया जा सके।

सरकार ने महत्वाकांक्षी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त-पोषण हेतु “विकास वित्त संस्थानों” (Development Finance Institutions: DFIs) को पुनर्जीवित करने की योजना निर्मित की है

- हाल ही में, सरकार ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने वाली सरकार के स्वामित्वधीन एक कंपनी) को रूपांतरित कर इसे एक DFI में तब्दील करने के लिए अपनी इक्विटी पूंजी में 15,000 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
- DFI एक ऐसी संस्था है, जिसे सरकार द्वारा मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के एक या एक से अधिक क्षेत्रों या उप-क्षेत्रों को विकास वित्त (development finance) प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन या सहायता प्रदान की जाती है।
 - भारत में, DFIs की स्थापना मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्त की मांग को पूर्ण करने के लिए की गई थी।
- वर्ष 2000 और वर्ष 2010 के मध्य, ICICI, IDBI और IDFC जैसे DFIs ने अपने दीर्घकालिक वित्त को उद्योगों एवं ग्रीनफील्ड अवसंरचना परियोजनाओं तक विस्तारित किया था।
 - हालांकि, DFIs को अग्रलिखित कारणों से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था: अल्प लागत वाली निधियों का अभाव, जोखिम का उच्च संकेन्द्रण, दबावग्रस्त क्षेत्रों के प्रति उच्च जोखिम (जैसे- विद्युत उत्पादन)।
- DFIs को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता क्यों है?
 - वर्तमान में अवसंरचना वित्तीयन में बैंक ऋण का वर्चस्व है। जबकि, बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि देखी जा रही है।
 - संबंधित परिसंपत्ति-देयता असंतुलन के बिना दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं का वित्त-पोषण करने के लिए भी इसकी आवश्यकता महसूस की गयी है।
- नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, भारत को वर्ष 2030 तक अवसंरचना में निवेश के लिए लगभग 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development: MHRD) द्वारा डिजिटल शिक्षा पर

“इंडिया रिपोर्ट-2020” जारी की गई

- यह रिपोर्ट MHRD तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ एवं समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने तथा अधिगम अंतराल (learning gap) को कम करने के लिए अपनाई गई अभिनव विधियों को रेखांकित करती है।
 - कोविड-19 के कारण विद्यालयों का संचालन अवरुद्ध है, जिससे संपूर्ण भारत में 240 मिलियन से अधिक बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है।
 - इसके अतिरिक्त, हाल ही में MHRD ने डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता (PRAGYATA) दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- इस रिपोर्ट में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर, सतत अधिगम (continuous learning) को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा रही निम्नलिखित 3 व्यापक विधियों की पहचान की गयी है:
 - जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण उपलब्ध हैं, वहां लाइव कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसे 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अपनाया गया है।
 - जहां डिजिटल तकनीक पूर्णतया अनुपलब्ध है, उस संदर्भ में कम से कम 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में टेलीविजन के माध्यम से कक्षाओं का प्रसारण किया जा रहा है तथा 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रेडियो का उपयोग किया जा रहा है।
 - सर्वाधिक सुलभ दूरस्थ शिक्षा का प्रकार एसिंक्रोनस अर्थात् अनियमित डिजिटल शिक्षा है। इसके तहत दीक्षा (DIKSHA) जैसे प्लेटफॉर्म पर पहले से ही तैयार डिजिटल सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।
- इस रिपोर्ट में शिक्षा की दीर्घकालिक रणनीति के रूप में डिजिटल शिक्षा की परिकल्पना तथा कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित योजनाओं का उल्लेख किया गया है:
 - निर्देशात्मक साधन (Instructional modality) के रूप में डिजिटल कक्षाओं का विकास करना।
 - आभासी व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास पाठ्यक्रम आदि।
 - स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री विकसित करना।

मालदीव ने HICDP के तहत 9 विकास परियोजनाओं को प्रारंभ किया

- इन परियोजनाओं में मत्स्य-प्रसंस्करण संयंत्रों, अदु पर्यटन क्षेत्र (Addu Tourism Zone) आदि का विकास शामिल है।
- वर्ष 2019 में, भारत और मालदीव ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं (High Impact Community Development Projects: HICDPs) के तहत एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
 - इसके तहत, मालदीव में अनुदान राशि की सहायता से परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए 5.6 मिलियन डॉलर का कुल अनुदान घोषित किया गया था।
 - साथ ही, लघु परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लगभग 7 मिलियन डॉलर के नकद अनुदान (cash grant) की भी घोषणा की गयी थी।
- HICDPs के अंतर्गत ऐसी परियोजनाएं शामिल होती हैं जिनका सामुदाय पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव होता है। इसमें आजीविका एवं आय सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक और बाल सशक्तीकरण, खेल, संधारणीय विकास आदि क्षेत्रों में भागीदारी शामिल होती है।
 - भारत ने अफगानिस्तान, भूटान आदि देशों के साथ भी HICDPs पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत द्वारा हाल ही में मालदीव में प्रारंभ की गई पहलें:
 - ऑपरेशन संजीवनी: इसके तहत, भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं और 800 टन खाद्य सामग्री प्रदान की है।
 - SBI द्वारा मालदीव को कोविड-राहत: इसके अंतर्गत मालदीव में स्थानीय व्यवसायों को तरलता सहायता प्रदान की जा रही है।
- भारत के लिए मालदीव का महत्व:
 - भारत के पश्चिमी तट से अत्यधिक निकट होने के कारण रणनीतिक महत्व आदि,
 - यह हिंद महासागर के माध्यम से संचालित वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के केंद्र में स्थित है।



अन्य सुर्खियाँ

वित्त वर्ष 2020 में वस्तु एवं सेवा कर "प्रतिकर उपकर" संग्रह में 42% की कमी आई है (Goods and Services Tax (GST) compensation cess falls 42% short in FY20)	○ वर्ष 2019-20 के दौरान, केवल 95,444 करोड़ रुपये का उपकर संग्रह हुआ, जो राज्यों को भुगतान किए गए 1.65 लाख करोड़ रुपये का केवल 58% था। ○ GST प्रतिकर उपकर (Compensation Cess) एक ऐसा उपकर है, जिसे कुछ विलासितापूर्ण एवं डीमेरिट वस्तुओं (demerit goods) और सेवाओं पर अधिरोपित किया जाता है। ○ इसका उपयोग राज्यों को प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) का भुगतान करने के लिए किया जाता है। ○ GST अधिनियम में राज्यों को एक गारंटी प्रदान की गई है कि इसके कार्यान्वयन के पहले पांच वर्षों में (वर्ष 2017-2022) यदि GST राजस्व संग्रह में वृद्धि 14 प्रतिशत से कम रहती है तो उस हानि की भरपाई GST क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से की जाएगी।
सरकार ने NRIs के लिए एयर इंडिया में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है (Govt notifies 100% foreign direct investment (FDI) in Air India for NRIs)	○ सरकार ने विदेशी विनियम प्रबंधन नियमों (Foreign Exchange Management rules) में संशोधन करते हुए, अनिवासी भारतीयों (Non-Resident Indian: NRI) को एयर इंडिया में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति प्रदान की है। ➤ इससे पूर्व, विमानन क्षेत्र में NRIs के लिए FDI की उच्चतम सीमा 49% थी। ○ इस कदम का उद्देश्य एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को और अधिक आकर्षक बनाना है। ➤ सरकार ने एयर इंडिया की अपनी संपूर्ण हिस्सेदारी की बिक्री करने की योजना बनायी है।
बागजान तेल कुआं, असम (Baghjan Oil Well, Assam)	○ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal: NGT) द्वारा गठित समिति ने मई 2020 में असम के बागजान तेल कुएँ में आग लगने की घटना के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड को दोषी ठहराया है। ○ यह भी उल्लेखित किया गया है कि आग लगने से मगुरी-मोटापुंग आर्द्रभूमि (Maguri-Motapung wetland) और डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान (Dibru-Saikhowa National Park) दोनों को व्यापक क्षति पहुंची है। ➤ मगुरी-मोटापुंग आर्द्रभूमि एवियन (पक्षियों) और जलीय प्रजातियों के पर्यावास हेतु विख्यात है। यह स्थल इस तेल कुएँ के दक्षिण में स्थित है। ➤ डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह उद्यान इस तेल कुएँ के उत्तर में लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दो पहलों का शुभारंभ (Ministry of Earth Sciences (MoES) launches two initiatives)	○ नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क (KRCNet): ➤ इसका उद्देश्य ज्ञान आधारित उत्पादों, जैसे- पुस्तक, रिपोर्ट्स, जर्नल्स आदि के लिए सिंगल-प्वाइंट 24x7 पहुँच प्रदान करने हेतु एक एकीकृत सूचना प्रणाली विकसित करना है। ➤ इसका निष्पादन डिजिटल इंडिया पहल के तहत किया जाएगा। ➤ MoES के पारंपरिक पुस्तकालयों को KRC में अपग्रेड किया जाएगा। ○ भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के लिए "मौसम" नामक एक मोबाइल ऐप: ➤ यह मौसम की सूचना और पूर्वानुमान को तकनीकी शब्दावली के बिना सरल तरीके से प्रसारित करेगा। ➤ इसमें निम्नलिखित 5 सेवाएं सम्मिलित हैं: वर्तमान मौसम (Current Weather) की जानकारी, नाऊकास्ट (Nowcast) (अर्थात् स्थानीय मौसम के बारे में प्रति घंटा चेतावनी), किसी शहर के मौसम के बारे में पूर्वानुमान (City Forecast), तथा चेतावनी और रडार उत्पाद।
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)	○ वित्त मंत्री ने AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। ○ AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका प्रमुख उद्देश्य एशिया में सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को उन्नत करना है। ○ भारत AIIB का एक संस्थापक सदस्य है। AIIB में भारत दूसरा सबसे बड़ा शेरधारक है, तथा इसके मत का भारांश 7.5 प्रतिशत है। जबकि, चीन इसका सबसे बड़ा शेरधारक है तथा उसके मत का भारांश 26.06 प्रतिशत है। ○ AIIB की स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में अवस्थित है।
ओकावांगो डेल्टा, बोत्सवाना (Okavango Delta, Botswana)	○ हाल ही में, ओकावांगो डेल्टा क्षेत्र में हाथियों के काफी संख्या में शव पाए गए थे। हालाँकि, सरकार ने इन हाथियों की मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। ➤ बोत्सवाना (अफ्रीका महाद्वीप का एक देश) में विश्व की सबसे अधिक हाथियों की आबादी (लगभग 1,30,000) पाई जाती है। ○ यह डेल्टा बोत्सवाना के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित है। इसमें स्थायी दलदली भूमि एवं मौसमी बाढ़कृत मैदान शामिल हैं। ➤ यह एक आंतरिक डेल्टा प्रणाली (interior delta system) है, जो समुद्र या महासागर में विलीन नहीं होती है। ➤ इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर (World Heritage) स्थलों की सूची के साथ-साथ रामसर स्थल (Ramsar site) के रूप में भी घोषित किया गया है।
यांग्त्ज़ी नदी, चीन (Yangtze river, China)	○ नासा (NASA) द्वारा ली गई तस्वीरों (images) ने यांग्त्ज़ी नदी के ऊपर निर्मित थ्री गॉर्जस डैम (Three Gorges Dam) से बाढ़ के जल को प्रसारित होते हुए दर्शाया है। ○ यांग्त्ज़ी एशिया की सबसे लंबी नदी है। थ्री गॉर्जस डैम विश्व का सबसे बड़ा जलविद्युत बांध है।